<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

1. संसद का मानसून सत्र, 2023, जो गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 से आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 23 दिनों की अवधि में 17 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान, लोक सभा में 20 विधेयक और राज्य सभा में 5 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 22 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 25 विधेयक पारित किए गए। लोक सभा और राज्य सभा की अनुमति से दोनों में एक-एक विधेयक वापिस लिया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 23 है।

3. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

4. मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए एक अध्यादेश अर्थात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेने वाले विधेयक पर दोनों सदनों द्वारा विचार और पारित किया गया जिसका उद्देश्य स्थानांतरण, तैनाती, सतर्कता और अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर उप-राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किए जाने वाले एक स्थायी प्राधिकरण के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के आशय और प्रयोजन को लागू करना है।

5. सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:

- **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023** फिल्म चोरी की जांच करने, प्रमाणन की आयु-आधारित श्रेणियां प्रस्तुत करने और मौजूदा अधिनियम में अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए अधिनियम में सक्षम उपबंधों को शामिल करके प्रदर्शन हेतु फिल्मों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी तथा बदले हुए समय के अनुरूप करने की मांग करता है।

- **संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2023** सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का उपबंध करता है।

- **संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2023** भूईंया, भूईयां और भूयां समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय के पर्याय के रूप में शामिल करने की मांग करता है। इसमें छत्तीसगढ़ में पांडो समुदाय के नाम के तीन देवनागरी संस्करण भी शामिल हैं।

- **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023** (i) मौजूदा कानून में संशोधन करके बहुराज्य सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करके जवाबदेही को बढ़ाकर और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता में वृद्धि करने और (ii) निगरानी तंत्र में सुधार करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने की मांग करता है।

- **जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023** (i) औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करने; (ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने; (iii) जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और इसके नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों से समझौता किए बिना भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करने; (iv) कुछ प्रावधानों को अपराधमुक्त करने; (v) राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने की मांग करता है।

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** अन्वेषण लाइसेंस आरंभ करने और परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों को हटाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने की मांग करता है।

- **अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन प्रक्रिया के माध्यम से संक्रिया अधिकारों के शीघ्र आवंटन को सक्षम करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में प्रतियोगी बोली द्वारा केवल नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन पट्टे का उपबंध करता है। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की अन्य विशेषताओं को अपनाने की भी मांग करता है, जैसे खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्यास की स्थापना और खोज को प्रोत्साहित करना, वैवेकिक नवीकरण की प्रक्रिया को हटाना और पचास वर्ष की एक समान पट्टा अवधि प्रदान करना।

- **वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023** अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की भूमियों में अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करके और अधिनियम के तहत अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की बात करता है।

- **जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023** गौण अपराधों के निरापराधीकरण के अतिरिक्त अपराध की गंभीरता पर निर्भर करते हुए धनीय शास्तियों को युक्तियुक्त बनाने और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। विधेयक के कानून बनने के पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के अवसान पर उद्गृहीत जुर्माने और शास्ति की न्यूनतम रकम में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधेयक में अंतर्वलित एक नवनूतनता है।

- **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023** का उद्देश्य पिछले पांच दशकों के दौरान समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों को समायोजित करने, पंजीकरण प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने और पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य डेटाबेस को अद्यतन करना है।

- **मध्यकता विधेयक, 2021** का उद्देश्य वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान के लिए, विशिष्टतया संस्थागत मध्यकता का उन्नयन करने, प्रोत्साहन देने और सुकर बनाने, मध्यकता किए गए समझौता करारों को प्रवृत करने, मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक निकाय का उपबंध करने, समुदायिक मध्यकता को प्रात्साहित करने और किसी प्रतिग्राह्य तथा लागत की प्रभावी प्रक्रिया के रूप में ऑनलाइन मध्यकता को बढ़ावा देने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है।

- **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023** सेवा कार्मिक, जिन पर सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेवा संगठनों के चीफ कमांडर या कमान आफिसर को सशक्त करने का उपबंध करता है।

- **भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023** का उद्देश्य (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को अधिशासित करने वाले अधिनियमों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम का अनुयोजन करना, (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की अनुसूची में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई का अंतर्वेशन एवं राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई का नाम बदलकर भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई करना है।

- **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023** का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करना, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करना, उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है।

- **राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023** का उद्देश्य परिचर्या और प्रसूति विद्या पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन और रखरखाव करना, संस्थानों का मूल्यांकन, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों का रखरखाव और पहुंच, अनुसंधान और विकास में सुधार एवं नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति को अपनाने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए एक प्रणाली का निर्माण करना है।

- **संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023** का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 33 पर महार, मेहरा, मेहर के समानार्थी महरा, महारा समुदाय का समावेशन करना है।

- **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023** का उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावर्णीय और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल है, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश देने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथापेक्षित प्रोत्साहन देने, निगरानी करने और सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना करना है।

- **डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023** डिजिटल वैयक्तिक डाटा का ऐसी रीति में प्रकमण का उपबंध करने की मांग करता है, जो लोगों के वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता के अधिकार और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को मान्यता देता हो।

- **तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023** का उद्देश्य (क) अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करता है ताकि तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना हितधारकों के विनियामक अनुपालन भार को कम किया जा सके, (ख) अधिनियम के तहत अपराध (अपराधों) का गैर-अपराधीकरण करना; (ग) सभी तटीय जलकृषि गतिविधियों को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करना; और (घ) प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापारिक सुगमता के लिए अधिनियम में जटिलताओं और विनियामक अंतराल को दूर करना है।

- **भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023** प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या उक्त अधिनियम के अधीन जो विहित योग्यता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) रखता है, को उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अधीन रहते हुए दर्ज किया गया समझा जाएगा कि भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित कोई आवेदन ऐसी फीस का संदाय करने और ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किया जाए।

6. मंत्रिपरिषद में श्री गौरव गोगोई द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 20 घंटे चर्चा हुई। चर्चा में मंत्रियों सहित 60 सदस्यों ने भाग लिया, जिसका माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया। प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से अस्वीकृत किया गया।

7. लोक सभा की उत्पादकता लगभग 45% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 63% रही।

17वीं लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 260वें सत्र (मानसून सत्र) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
2. राष्ट्रीय दंत-चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
3. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
4. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
5. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
6. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.
7. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
8 संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
9. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
10. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
11. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
12. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
13. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
14. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
15. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
16. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
17. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
18. भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023
19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023
20. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
2. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
3. प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
4. डाकघर विधेयक, 2023
5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
3. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
4. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
7. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
8. राष्ट्रीय दंत-चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
9. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023

* संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2023
* संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2023
10. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
11. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
12. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
13. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
14. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
15. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
16. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
17. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
18. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
19. मध्यकता विधेयक, 2023
20. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
21. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
22. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
3. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
4. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023
5. मध्यकता विधेयक, 2021
6. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
8. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
9. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
10. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
11. प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
12. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
13. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
14. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
15. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
16. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
17. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
18. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
19. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
20. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
21. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
22. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
23. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
24. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
25. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2023
3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2023
4. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023
5. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
7. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
9. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
10. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
11. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
12. मध्यकता विधेयक, 2023
13. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
14. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
15. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
16. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
17. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
18. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
19. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
20. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
21. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
22. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
23. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

VI. लोक सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019

VII. राज्य सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019